Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

05-06 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NCMM के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

सितंबर 2025 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने और उत्पादन करने के लिए भारत की पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ाना है।

- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के तहत शुरू की गई यह पहल घरेलू क्षमता, स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को मजबूत करने पर केंद्रित है।**

- **नई स्वीकृत योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) से शुरू होकर वित्त वर्ष 31 तक, छह वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। यह दीर्घकालिक संरचना पुनर्चक्रण उद्योगों को निरंतर समर्थन सुनिश्चित करती है, जो महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति में आत्मनिर्भरता और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।**

- **इस योजना के अंतर्गत पात्र फीडस्टॉक में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा), लिथियम-आयन बैटरी (LIB) स्क्रैप, और अन्य उच्च-मूल्य वाली श्रेणियाँ, जैसे कि जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों से निकलने वाले उत्प्रेरक कन्वर्टर्स शामिल हैं। ये सामग्रियाँ लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरपूर हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल तकनीकों के लिए आवश्यक हैं।**

Key Points:-

(i) इस योजना के लाभार्थियों में स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता और नए प्रवेशकर्ता, दोनों शामिल होंगे, और पुनर्चक्रण एवं खनिज निष्कर्षण पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप्स पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। विविध हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और पुनर्चक्रण उद्योग का विस्तार करना है।

(ii) समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, कुल बजट परिव्यय का एक-तिहाई (33.33%) छोटी संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि छोटे पैमाने के पुनर्चक्रणकर्ता और उभरते उद्यम समान रूप से लाभान्वित हो सकें, जिससे भारत में एक संतुलित और प्रतिस्पर्धी पुनर्चक्रण क्षेत्र का निर्माण हो सके।

(iii) NCMM के तहत यह प्रोत्साहन योजना सतत संसाधन उपयोग और आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता को कम करने पर भारत के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (BRJNSSSL) का उद्घाटन किया।

सितंबर 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई सहकारी वित्तीय पहल, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (BRJNSSSL) का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने जीविका निधि के बैंक खाते में ₹105 करोड़ हस्तांतरित करके संस्था की गतिविधियों की शुरुआत की।

• विश्व बैंक (WB) से वित्तीय सहायता के साथ 2007 में शुरू किया गया जीविका कार्यक्रम, बिहार की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित आजीविका पहल के रूप में विकसित हो गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सहायता प्रदान करता है।

• बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP), जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) द्वारा किया जाता है, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

• पिछले कुछ वर्षों में, जीविका के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन कई महिलाएँ अभी भी 18% से 24% के बीच ऊँची ब्याज दर वसूलने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इस निर्भरता को कम करने और बड़े ऋणों तक किफ़ायती पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, राज्य ने वैकल्पिक ऋण प्रणाली के रूप में जीविका निधि पहल शुरू की।

Key Points:-

(i) बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड (BRJNSSSL) की स्थापना राज्य भर में वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जीविका के पंजीकृत क्लस्टर-स्तरीय संघों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना है, जो सहकारी समिति के मुख्य सदस्य होंगे। यह प्रयास राज्य के सतत, महिला-नेतृत्व वाली उद्यमिता और वित्तीय आत्मनिर्भरता को सक्षम बनाने के मिशन के अनुरूप है।

(ii) बिहार सरकार ने BRJNSSSL के लिए कुल ₹1,000 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिससे इसकी गतिविधियों को एक मज़बूत वित्तीय आधार मिलेगा। यह महत्वपूर्ण आवंटन मज़बूत तरलता सहायता और पहुँच क्षमता सुनिश्चित करता है, जिससे बिहार भर में हज़ारों जीविका दीदियों को लाभ होगा। इस सहकारी संस्था से ग्रामीण महिलाओं की निजी ऋणदाताओं पर वित्तीय निर्भरता कम करने और सामुदायिक उद्यमों के पैमाने का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

(iii) कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, BRJNSSSL पूरी तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा, जिससे जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे त्वरित और पारदर्शी धनराशि हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे क्रियान्वित करने के लिए, 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें निर्बाध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। यह पहल बिहार के महिला-केंद्रित विकास दृष्टिकोण में एक मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता और समुदाय-आधारित उद्यम विकास में बदलाव लाना है।

3. प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री वांग यी ने जेएन पोर्ट पर पीएसए मुंबई टर्मिनल के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने 4 सितंबर, 2025 को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर पीएसए द्वारा संचालित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (BMCT) के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह विस्तार भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक बड़ी छलांग है।

- **BMCT के दूसरे चरण में टर्मिनल की हैंडलिंग क्षमता 2.4 मिलियन से बढ़कर 4.8 मिलियन बीस-फुट समतुल्य इकाई (TEUs) हो जाएगी, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा स्टैंडअलोन कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा।**

- **PSA इंटरनेशनल के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित, सिंगापुर ने भारत में अपना सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किया है, जो कुल मिलाकर लगभग 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1.7 बिलियन सिंगापुर डॉलर) है।**

- **उन्नत टर्मिनल 200 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें 2,000 मीटर का सतत घाट है, और यह उच्च तकनीक वाले बंदरगाह संचालन बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है, जिसमें 24 घाट क्रेन, 72 रबर-टायर वाले गैन्ट्री क्रेन, रेल-माउंटेड गैन्ट्री क्रेन और गहरे ड्राफ्ट वाले बर्थ शामिल हैं, जो 18,000 TEUs तक के मेगा जहाजों को समायोजित करने में सक्षम हैं।**

Key Points:-

(i) 100% नवीकरणीय ऊर्जा टर्मिनल के रूप में डिज़ाइन किया गया, BMCT चरण II भारत के हरित और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भी है। यह समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC) के अनुरूप रेल संपर्कों को एकीकृत करता है, जिसमें छह ट्रैक जेएन पोर्ट को 63 से अधिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICDs) से जोड़ते हैं, जिससे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होता है।

(ii) इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, PSA इंडिया के प्रबंध निदेशक गोबू सेलियाया और JNPA के अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ जैसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह विस्तार किस प्रकार महाराष्ट्र की राष्ट्रीय समुद्री महाशक्ति के रूप में स्थिति को मज़बूत करेगा और वैश्विक मंच पर भारत की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

4. APEDA ने कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए भारती पहल शुरू की।

सितंबर 2025 में, वाणिज्य विभाग (DoC), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने भारत के कृषि-खाद्य निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और कृषि-तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'भारती' पहल शुरू की।

• भारत के कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र (BHARATI) नामक इस पहल का अनावरण नई दिल्ली में खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र के हितधारकों की बैठक के दौरान किया गया।

• बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की, जिन्होंने भारत को कृषि निर्यात में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया।

• BHARATI को 100 कृषि-खाद्य और कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कृषि पद्धतियों, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों में नवाचार को प्रोत्साहित करेंगे। इन स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इनक्यूबेशन, मेंटरिंग और वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

Key Points:-

(i) यह पहल APEDA की दीर्घकालिक निर्यात रणनीति के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अपने निर्धारित उत्पादों के लिए 50 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कृषि-खाद्य निर्यात को प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का सामना करने और कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण पर केंद्रित है।

(ii) BHARATI उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों जैसे भौगोलिक संकेत (GI)-टैग वाले उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड, नवीन प्रसंस्कृत कृषि-खाद्य पदार्थ, पशुधन-आधारित उत्पाद और आयुष (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी) उत्पादों को प्राथमिकता देगी। इससे भारत के निर्यात में विविधता आएगी और साथ ही स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी।

(iii) सितंबर 2025 में शुरू की गई इस पहल का पहला पायलट समूह उच्च-मूल्य वाले कृषि-खाद्य उत्पादन और प्रौद्योगिकी-संचालित सेवाओं में लगे स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करेगा। ऐसा करके, APEDA का लक्ष्य युवा उद्यमियों के लिए एक मज़बूत मंच तैयार करना, भारत के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है।

5. AQLI 2025 रिपोर्ट: वायु प्रदूषण से भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कम, दिल्ली-NCR सबसे ज्यादा प्रभावित।

शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) की हालिया वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (AQLI) 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि वायु प्रदूषण अब भारत के लिए सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, जिससे औसत जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कम हो रही है। यह स्पष्ट निष्कर्ष प्रभावी स्वच्छ वायु नीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

• 2023 कण पदार्थ ($PM_{2.5}$) डेटा का उपयोग करते हुए AQLI विश्लेषण से पता चलता है कि सभी 1.4 बिलियन भारतीय विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षित सीमा 5 µg/m³ से अधिक हवा में सांस लेते हैं, और कणिकीय स्तर भारत की लगभग आधी आबादी के लिए 40 µg/m³ के अपने मानक से अधिक है, जिससे व्यापक स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है।

• उत्तरी मैदान दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्र के रूप में उभरे हैं, जहां लगभग 544 मिलियन लोग - भारत की 38.9% आबादी - खतरनाक रूप से खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक क्षेत्रीय नुकसान हुआ है।

Key Points:-

(i दिल्ली-NCR क्षेत्र के निवासी असमान रूप से प्रभावित हैं, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु मानकों की तुलना में जीवन प्रत्याशा 8.2 वर्ष तक कम हो गई है; यहां तक कि भारत की राष्ट्रीय सीमा के तहत भी, उनकी जीवन प्रत्याशा में 4.74 वर्ष की कमी आई है, जो राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता को रेखांकित करता है।

(ii) अन्य प्रमुख खतरों की तुलना में, वायु प्रदूषण का प्रभाव उनसे कहीं अधिक है: यह जीवन प्रत्याशा को बचपन और मातृ कुपोषण (1.6 वर्ष) की तुलना में लगभग दोगुना कम करता है, तंबाकू के उपयोग (1.5 वर्ष) की तुलना में तीन गुना से अधिक, और असुरक्षित जल और स्वच्छता (~ 8.4 महीने) की तुलना में पांच गुना से अधिक कम करता है।

(iii) भारत के चल रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) और अन्य प्रयासों के बावजूद, 2023 में प्रदूषण का स्तर 2.8% बढ़ गया, जिससे दक्षिण एशिया विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया। रिपोर्ट में इस प्रवृत्ति को उलटने और जन स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए तत्काल और महत्वाकांक्षी उपायों का आह्वान किया गया है।

6. GST परिषद ने कर स्लैब को घटाकर दो (5% और 18%) कर दिया, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।

एक ऐतिहासिक सुधार के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढांचे को सुव्यवस्थित करते हुए चार मौजूदा कर स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब—5% और 18%—कर दिया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाने और मध्यम वर्ग पर बोझ कम करने के उद्देश्य से किया गया यह बदलाव 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा।

• GST में व्यापक बदलाव के तहत 12% और 28% की दरों को खत्म करके कई दरों को 5% ("निम्न" या "योग्यता") और 18% ("मानक") श्रेणियों में समेकित किया जाएगा। तंबाकू, मीठे पेय, महंगे वाहन और नौकाओं जैसी हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40% की उच्च दर लागू रहेगी। इन सुधारों का उद्देश्य "जनता का सुधार" है और इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लाभ होगा—खासकर आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को।

• कर संशोधन से खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, दवाओं, व्यक्तिगत देखभाल, उपभोक्ता

टिकाऊ वस्तुओं और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। बेहतर सामर्थ्य के कारण FMCG, जूते-चप्पल, किराना, त्वरित सेवा वाले रेस्टोरेंट (QSR) और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में मांग में तेजी आने की संभावना है।

• इस सुधार ने निवेशकों का उत्साह पहले ही बढ़ा दिया है—भारत के शेयर बाजारों में इसकी प्रतिक्रिया में तेज़ी आई है, और ऑटो, उपभोक्ता वस्तुओं और मिड-कैप क्षेत्रों में भी बढ़त दर्ज की गई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस सरलीकरण से अगली कुछ तिमाहियों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 100-120 आधार अंक (लगभग 1-1.2%) की वृद्धि हो सकती है।

Key Points:-

(i) GST में कटौती दिवाली से पहले त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, जिससे परिवारों को बजट में राहत मिलेगी और अनुपालन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) जैसे उद्योग निकायों ने इस सुधार का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

(ii) हालांकि इस कदम से अस्थायी राजस्व हानि होगी—अनुमानतः ₹48,000 करोड़—वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह वित्तीय रूप से टिकाऊ है। सरकार ने राजस्व प्रवाह बनाए रखने और दीर्घकालिक प्रभाव को कम करने के लिए रिफंड और MSME अनुपालन को सरल बनाने जैसे उपायों का वादा किया है।

7. IIT मद्रास लगातार सातवें वर्ष NIRF 2025 रैंकिंग में शीर्ष पर है और इंजीनियरिंग और SDG श्रेणियों में अग्रणी है।

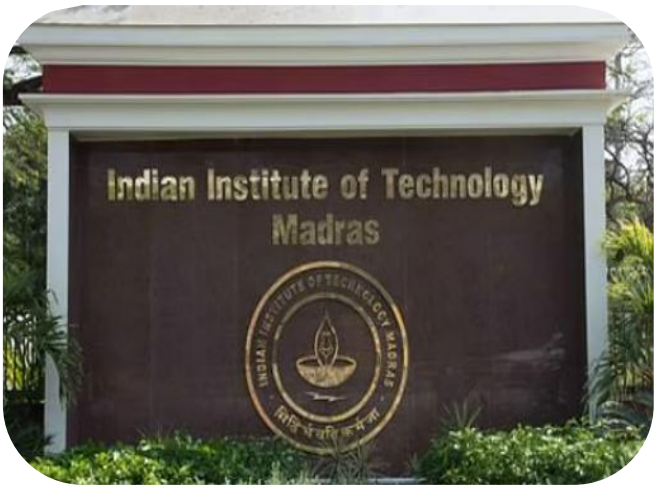

एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास ने लगातार सातवें वर्ष राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के प्रति IIT मद्रास की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

• IIT मद्रास ने 2019 से NIRF समग्र श्रेणी में नंबर एक संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है, जो शिक्षण, सीखने और संसाधन (TLR), अनुसंधान और व्यावसायिक प्रथाओं (RPC), स्नातक परिणाम (GO), आउटरीच और समावेशिता (OI), और धारणा सहित विभिन्न मापदंडों पर अपने निरंतर प्रदर्शन को दर्शाता है।

• समग्र श्रेणी के अलावा, IIT मद्रास ने विशिष्ट क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इंजीनियरिंग श्रेणी में इसने IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली जैसे संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, IIT मद्रास ने हाल ही में शुरू की गई सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) श्रेणी में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• हालाँकि IIT मद्रास ने अनुसंधान श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, फिर भी यह अभूतपूर्व अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है। उच्च-गुणवत्ता वाले प्रकाशनों, बौद्धिक संपदा सृजन और वैश्विक

सहयोग पर संस्थान के ध्यान ने शैक्षणिक समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा को मज़बूत किया है।

Key Points:-

(i) IIT मद्रास का नवाचार पर ज़ोर इसकी अत्याधुनिक सुविधाओं और उद्यमशीलता के लिए समर्थन से स्पष्ट है। संस्थान का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र रचनात्मकता और व्यावहारिक समस्या-समाधान को बढ़ावा देता है, जो नवाचार श्रेणी में इसकी शीर्ष रैंकिंग में योगदान देता है।

(ii) NIRF 2025 में IIT मद्रास की लगातार शीर्ष रैंकिंग भारत में एक प्रमुख संस्थान के रूप में इसकी स्थिति को और पुख्ता करती है। भविष्य में, IIT मद्रास का लक्ष्य अंतःविषय अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और सतत विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी वैश्विक उपस्थिति को और बढ़ाना है।

8. धर्मेन्द्र प्रधान और अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थान के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

3 सितंबर, 2025 को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थापन हेतु दिशानिर्देश जारी किए। यह रूपरेखा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और आधारभूत शिक्षा को सुदृढ़ बनाना है।

- **नए दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 तक बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी सुनिश्चित करना है। ये दिशानिर्देश 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों में शैक्षिक तैयारी और समग्र विकास दोनों को बढ़ावा देने वाले प्रेरक और आनंददायक शिक्षण वातावरण बनाने पर ज़ोर देते हैं।**

- **ये दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE&L) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं। यह सहयोग शिक्षा और बाल विकास प्रयासों को जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि सह-स्थान नीति व्यापक, समावेशी और राष्ट्रीय शिक्षा एवं बाल कल्याण लक्ष्यों के अनुरूप हो।**

- **आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थान देने के लिए दो अलग-अलग मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं। पहला मॉडल, "भौतिक सह-स्थान", बुनियादी ढाँचे की अनुमति मिलने पर आंगनवाड़ी केंद्रों को सीधे स्कूल परिसर में एकीकृत करता है। दूसरा मॉडल, "नज़दीकी स्कूलों का मानचित्रण", उन क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों को, जहाँ पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, प्रभावी संक्रमण के लिए निकटतम उपलब्ध स्कूल से जोड़ने की अनुमति देता है।**

Key Points:-

(i) ये दिशानिर्देश दोनों मंत्रालयों की मौजूदा प्रमुख पहलों को एकीकृत करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के निपुण भारत मिशन (समझ और अंकगणित के साथ पठन में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल, पोषण भी पढ़ाई भी के साथ जोड़ा

गया है। यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता और अंकगणित कौशल के साथ-साथ बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के अवसरों का भी लाभ मिले।

(ii) आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के बीच प्रारंभिक संपर्क को बढ़ावा देकर, ये दिशानिर्देश स्कूल की तैयारी को बढ़ाते हैं, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। सह-स्थानीकरण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय भी संभव होगा, जिससे शिक्षण पद्धति में निरंतरता, बेहतर निगरानी और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा।

(iii) यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और बुनियादी साक्षरता को सीखने के परिणामों के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में महत्व देती है। इस पहल के साथ, सरकार भविष्य में सीखने के लिए मज़बूत नींव तैयार करने के साथ-साथ एक समग्र ढाँचे के माध्यम से बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और विकासात्मक आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहती है।

9. भारत ने 7 वर्षों के अनुसंधान के बाद पहली स्वदेशी जल-घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित की।

सितंबर 2025 में, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी जल-घुलनशील उर्वरक तकनीक विकसित करके एक बड़ी सफलता हासिल की। 7 वर्षों के गहन शोध के बाद हासिल किया गया यह नवाचार, विशिष्ट उर्वरकों के क्षेत्र में आयात निर्भरता से निर्यात क्षमता की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसका व्यावसायिक उत्पादन दो वर्षों के भीतर किसानों तक पहुँचने की उम्मीद है।

- **इस तकनीक को मेक इन इंडिया पहल के तहत एक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इसे पूरी तरह से भारतीय कच्चे माल और भारतीय डिज़ाइन वाले संयंत्रों से विकसित किया गया है। खान मंत्रालय (MoM) द्वारा समर्थित, यह उच्च-मूल्य वाली कृषि सामग्री के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।**

- **इस विकास का नेतृत्व घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ (SFIA) के अध्यक्ष राजीब चक्रवर्ती ने किया। उनके नेतृत्व और भारतीय शोधकर्ताओं तथा उद्योग के हितधारकों के संयुक्त प्रयासों ने इस स्वदेशी उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**

Key Points:-

(i) वर्तमान में, भारत की लगभग 80% विशिष्ट उर्वरक माँग आयात के माध्यम से पूरी होती है, मुख्यतः चीन से। इस स्वदेशी जल-घुलनशील उर्वरक तकनीक के आगमन से, भारत के चीनी आयात पर अपनी निर्भरता में भारी कमी आने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की उम्मीद है।

(ii) नई तकनीक न केवल निर्भरता कम करती है, बल्कि भारत के लिए विशिष्ट उर्वरकों के निर्यातक के रूप में उभरने के रास्ते भी खोलती है। आयात-आधारित से निर्यात-प्रधान राष्ट्र बनकर, भारत वैश्विक कृषि इनपुट बाज़ार में अपनी स्थिति को काफ़ी मज़बूत कर सकता है।

(iii) इस उर्वरक प्रौद्योगिकी को शून्य-उत्सर्जन,

उत्सर्जन-मुक्त परियोजना के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के सतत कृषि पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसकी पर्यावरण-अनुकूल विशेषताएँ इसे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करते हुए बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

10. नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने "2D मैटेरियल्स" पर 4वां फ्यूचर फ्रंट इनसाइट्स जारी किया।

4 सितंबर 2025 को, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब (FTH) ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के सहयोग से "2D सामग्रियों का परिचय" शीर्षक से अपने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स के चौथे संस्करण को लॉन्च किया, जिसमें अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के अवसर पर प्रकाश डाला गया।

• यह रिपोर्ट नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में जारी की गई, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को 2D सामग्रियों में शीघ्र निवेश करके अर्धचालकों में तकनीकी संप्रभुता हासिल करनी चाहिए, जो स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत और तांबे से अधिक सुचालक हैं।

• फ्रंटियर टेक हब की मुख्य वास्तुकार देबजानी घोष ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व अब आपूर्ति श्रृंखलाओं, मानकों और गठबंधनों को नियंत्रित करने पर निर्भर करता है, और भारत को दूसरों का अनुसरण करने के बजाय सेमीकंडक्टर परिदृश्य को आकार देने के लिए 2डी सामग्रियों को अपनाना चाहिए।

• IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि लाइसेंस प्राप्त अर्धचालक प्रौद्योगिकी पर निर्भरता भेद्यता पैदा करती है, और भारत को बड़े पैमाने पर 2D सामग्री अनुप्रयोगों के माध्यम से स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) विकसित करनी चाहिए।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले से ही 2D सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि भारत अभी शुरुआती चरण में है और मुख्य रूप से संश्लेषण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वेफर-स्तरीय नवाचार और विनिर्माण की ओर बढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता है।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों के लिए आह्वान करना शुरू कर दिया है, जो भारत के 2D सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पहला संस्थागत धक्का है, जो भविष्य की अर्धचालक प्रौद्योगिकियों में ऊर्जा बचत, IP स्वामित्व और रणनीतिक स्वतंत्रता का वादा करता है।

INTERNATIONAL

1. नेपाल ने डिजिटल जवाबदेही लागू करने के लिए 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया।

4 सितंबर, 2025 को, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के नेतृत्व में नेपाल सरकार ने उन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने और स्थानीय संपर्क कार्यालय स्थापित करने में विफल रहे थे। इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंता जताते हुए विनियमन को मज़बूत करना है।

- **नेपाली अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और 25 अगस्त के मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (NTA) को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफार्मों तक पहुंच को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया।**

- **अनुपालन आवश्यकताओं में स्थानीय संपर्क, शिकायत निवारण कर्मियों की नियुक्ति और स्व-नियमन ढाँचे शामिल थे। टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बज़ और पोपो लाइव जैसे अनुपालन करने वाले प्लेटफ़ॉर्म प्रतिबंध से मुक्त थे।**

- **जैसे ही निष्क्रियता शुरू हुई, दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने सेवा व्यवधान में विसंगतियों की सूचना दी, कुछ क्षेत्रों में कुछ प्लेटफ़ॉर्म अनुपलब्ध हो गए। नेपाल इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ (ISPAN), तकनीकी निर्देशों के अनुसार, कई दिनों तक बंद रहने की प्रक्रिया का प्रबंधन कर रहा है।**

Key Points:-

(i) इस फैसले की काफी आलोचना हुई है। नागरिक समाज समूहों, मीडिया और राजनीतिक दलों—जिनमें सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य और विपक्षी नेता दोनों शामिल हैं—ने संभावित अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रतिबंध डिजिटल स्वतंत्रता को कमजोर करता है, ई-कॉमर्स को प्रभावित करता है और संचार को प्रतिबंधित करता है, खासकर विदेश में रहने वाले नेपालियों के लिए।

(ii) सरकार का कहना है कि प्रतिबंध अस्थायी हैं और प्लेटफ़ॉर्म पंजीकरण कराने और स्थानीय नियमों का पालन करने के बाद अपनी सेवाएँ फिर से शुरू कर सकते हैं। मंत्री गुरुंग ने ज़ोर देकर कहा कि पंजीकरण कराने और उनका पालन करने पर तुरंत प्रतिबंध बहाल हो जाएँगे।

(iii) मंत्री गुरुंग, मंत्रालय के अधिकारियों, NTA, दूरसंचार ऑपरेटरों और ISPs की एक बैठक में इस बात की पुष्टि हुई कि इन प्लेटफार्मों ने कई पंजीकरण नोटिसों की अनदेखी की है। उनका तर्क है कि यह कदम नेपाल के तेज़ी से डिजिटल होते समाज में सामग्री की जवाबदेही बढ़ाने, फर्जी पहचानों पर अंकुश लगाने और गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए ज़रूरी है।

2. WHO रिपोर्ट 2021: आत्महत्या विश्व स्तर पर हर 100 में से 1 से अधिक मौतों का कारण, 7.27 लाख मामले दर्ज।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2021 में दुनिया भर में आत्महत्या से अनुमानित 7,27,000 लोगों की मौत हुई—जो कुल वैश्विक मौतों का 1% से भी ज़्यादा है। रिपोर्ट में कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है, खासकर युवाओं की सुरक्षा के लिए, जिनके लिए आत्महत्या मृत्यु का एक प्रमुख कारण बनी हुई है।

• WHO की "2021 में विश्वव्यापी आत्महत्या: वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान" तथ्य पत्रक में बताया गया है कि 15-29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में आत्महत्या मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण था, जो इसे वैश्विक स्तर पर युवा दर्शकों के लिए सबसे अधिक दबाव वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं में से एक बनाता है।

• निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMICs) ने आत्महत्या के बोझ का खामियाजा उठाया, जो 2021 में सभी आत्महत्याओं का लगभग 73% था। यह असमानता संसाधन-विवश सेटिंग्स में उन्नत मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं की तत्काल आवश्यकता को इंगित करती है।

• हालाँकि वैश्विक आयु-मानकीकृत आत्महत्या दर में मामूली गिरावट आई है, जो 2019 में प्रति 100,000 पर 9.0 से घटकर 2021 में 8.9 हो गई है, फिर भी प्रगति अपर्याप्त है। इस गति से, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 3.4.2—जिसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में एक-तिहाई कमी लाना है—को प्राप्त करना ख़तरे में है। वर्तमान रुझान उस समय सीमा तक केवल लगभग 12% की कमी का संकेत देते हैं।

Key Points:-

(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस बात पर ज़ोर देता है कि हर आत्महत्या के लिए लगभग 20 आत्महत्या के प्रयास होते हैं, जो दुनिया भर में परिवारों और समुदायों को प्रभावित करने वाले व्यापक भावनात्मक संकट को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानसिक स्वास्थ्य और गैर-संचारी रोग विभाग की अंतरिम प्रमुख, देवोरा केस्टेल ने इस बढ़ते संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की।

(ii) इन प्रवृत्तियों को समझते हुए, विश्व स्वास्थ्य संगठन तत्काल, बहुक्षेत्रीय कार्रवाई का आह्वान करता है—खासकर युवाओं पर केंद्रित, जो असमान रूप से प्रभावित रहते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देना और कमज़ोर युवाओं के लिए जोखिम कारकों की रोकथाम शामिल है।

BANKING & FINANCE

1. UPI ने अगस्त 2025 में पहली बार 20 अरब मासिक लेन-देन का आंकड़ा पार किया

सितंबर 2025 में, वित्त मंत्रालय (MoF) के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ मिलकर घोषणा की कि भारत के

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) ने अगस्त 2025 में पहली बार 20 बिलियन से अधिक मासिक लेनदेन दर्ज किए।

• UPI ने अगस्त 2025 में 20.01 बिलियन मासिक लेनदेन दर्ज किए, जो भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने में एक महत्वपूर्ण छलांग है।

• UPI लेनदेन का कुल मूल्य 24.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो खुदरा और बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान दोनों में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) अगस्त 2024 की तुलना में, UPI लेनदेन में मात्रा में 34% की वृद्धि (14.9 बिलियन से 20.01 बिलियन तक) और मूल्य में 21% की वृद्धि (20.60 लाख करोड़ रुपये से 24.85 लाख करोड़ रुपये तक) देखी गई।

(ii) औसतन, प्लेटफॉर्म ने प्रतिदिन 645 मिलियन लेनदेन संसाधित किए, जिनका दैनिक निपटान मूल्य लगभग 80,177 करोड़ रुपये था।

(iii) इस उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय (MoF) और NPCI द्वारा की गई, जिससे भारत के डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ के रूप में UPI की भूमिका को बल मिला।

2. भारतीय निर्यातकों के लिए सुरक्षित और कुशल सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए FIEO ने BRISKPE के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3 सितंबर, 2025 को, भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (FIEO) ने भारतीय निर्यातकों के लिए तेज़, अनुपालन और सुरक्षित सीमा पार भुगतान की सुविधा प्रदान करने तथा डिजिटल व्यापार समाधानों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक कंपनी BRISKPE के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• इस समझौता ज्ञापन पर FIEO के महानिदेशक (DG) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. अजय सहाय और BRISKPE के सह-संस्थापक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) इंदुनाथ चौधरी ने हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम FIEO के नोडल अधिकारी प्रतीक नवले की उपस्थिति में नई दिल्ली स्थित निर्यात भवन में आयोजित हुआ।

• इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए तीव्र, सुरक्षित और अनुपालन योग्य सीमा-पार भुगतान की सुविधा प्रदान करना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्बाध वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित हो सके।

• इस सहयोग का उद्देश्य निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिजिटल भुगतान समाधान के बढ़ते महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

Key Points:-

(i) समझौता ज्ञापन के तहत, BRISKPE ज्ञान सत्रों

और आउटरीच पहलों के माध्यम से FIEO सदस्यों के साथ जुड़ेगा, तथा प्रौद्योगिकी-संचालित, अनुपालन-योग्य सीमा-पार भुगतान तंत्र पर अंतर्दृष्टि साझा करेगा।

(ii) यह पहल निर्यातकों को सरलीकृत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहण विधियों से परिचित कराएगी, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस (B2B), उपभोक्ता से बिजनेस (C2B) और बिजनेस टू उपभोक्ता (B2C) मॉडल शामिल हैं, जिससे वैश्विक व्यापार परिचालन में दक्षता बढ़ेगी।

ECONOMY & BUSINESS

1. मुकेश अंबानी ने मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं AGM में AI सब्सिडियरी और जियोपीसी की घोषणा की।

20 अगस्त, 2025 को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) मुंबई, महाराष्ट्र से वर्चुअल माध्यम से आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) मुकेश अंबानी ने की। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), नए उत्पादों के लॉन्च और रणनीतिक वैश्विक साझेदारियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

• मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि RIL की नई लॉन्च की गई AI सहायक कंपनी है, का औपचारिक रूप से अनावरण किया। इस इकाई का उद्देश्य भारत-केंद्रित, उद्यम-स्तरीय AI बुनियादी ढाँचा तैयार करना है, जिसका उद्देश्य सभी उद्योगों में संप्रभु क्षमताओं को मज़बूत करना है।

• अपनी AI पहलों को बढ़ाने के लिए, रिलायंस इंटेलिजेंस ने गूगल के साथ एक रणनीतिक समझौता किया है। दोनों मिलकर, गुजरात के जामनगर में एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र का निर्माण करेंगे, जो निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए रिलायंस के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र और जियो के डिजिटल नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

• मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स, इंक. (पूर्व में फ़ेसबुक) के साथ एक और महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की गई। दोनों कंपनियों ने 855 करोड़ रुपये (लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का एक संयुक्त उद्यम (JV) बनाया, जिसमें रिलायंस की 70% और मेटा की 30% हिस्सेदारी होगी। यह संयुक्त उद्यम बड़े पैमाने पर एंटरप्राइज़-ग्रेड AI समाधान प्रदान करने के लिए मेटा के ओपन-सोर्स लामा AI मॉडल का उपयोग करेगा।

Key Points:-

(i) वार्षिक आम बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित पर्सनल कंप्यूटिंग समाधान, जियोपीसी (JioPC) का भी अनावरण किया गया। जियोपीसी एक सामान्य टेलीविजन या डिस्प्ले स्क्रीन को क्लाउड-संचालित कंप्यूटर में बदल देता है, जिससे उपयोगकर्ता पारंपरिक डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदे बिना ही शक्तिशाली AI टूल्स का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) जियो सेट-टॉप बॉक्स, कीबोर्ड और माउस द्वारा संचालित, जियोपीसी पूरी तरह से जियो के क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर होस्ट किया गया है। एप्लिकेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर वर्चुअल रूप से वितरित किए जाते हैं, जिससे यह व्यक्तियों और उद्यमों के लिए एक स्केलेबल विकल्प बन जाता है। सब्सक्रिप्शन-

आधारित पे-एज़-यू-गो मूल्य निर्धारण मॉडल उपयोगकर्ताओं को मासिक शुल्क देकर कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुँचने की अनुमति देता है, जिससे उच्च-स्तरीय AI-संचालित कंप्यूटिंग अधिक किफायती हो जाती है।

(iii) ये घोषणाएं रिलायंस की महत्वाकांक्षा को उजागर करती हैं कि वह खुद को AI-संचालित डिजिटल बुनियादी ढांचे में अग्रणी के रूप में स्थापित करना चाहती है, साथ ही भारत में लाखों लोगों के लिए उन्नत कंप्यूटिंग तक सस्ती पहुंच का विस्तार करना चाहती है।

2. DPIIT ने स्टार्टअप और हेल्थकेयर इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ICICI बैंक और फाइजर के साथ साझेदारी की।

4 सितंबर, 2025 को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoC&I) ने दो महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं - एक उत्पाद-आधारित स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए ICICI बैंक के साथ और दूसरी Pfizer Inc. की भारतीय सहायक कंपनी Pfizer Limited के साथ, फंडिंग, इनक्यूबेशन और मेंटरशिप के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य सेवा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए।

• DPIIT और ICICI बैंक के बीच सहयोग का उद्देश्य भारत में उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स के विकास को गति देना है। यह पहल स्टार्टअप संचालन को मज़बूत करने और नवोन्मेषी उत्पादों को निखारने के लिए संरचित मार्गदर्शन, एक्सेलरेटर तक पहुँच और व्यवसाय विकास सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

• इस साझेदारी के तहत, ICICI बैंक स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन और कार्यान्वित करेगा। यह कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आयोजित किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप-बैंक के बीच निरंतर जुड़ाव, संसाधनों तक पहुँच और शुरुआती उद्यमियों के लिए अवसरों के विस्तार हेतु एक संरचित मंच सुनिश्चित होगा।

• फाइजर लिमिटेड के सहयोग से, DPIIT, फाइजर इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा-केंद्रित स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करेगा। यह पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी पर बढ़ते फोकस के अनुरूप है, जो फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सा उपकरणों में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देती है।

Key Points:-

(i) फाइजर इनोवेशन प्रोग्राम के तहत, चयनित DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ₹60 लाख तक का वित्तीय अनुदान मिलेगा। इन अनुदानों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करना और क्रांतिकारी समाधानों के व्यावसायीकरण में तेज़ी लाना है।

(ii) इस कार्यक्रम में एक प्रमुख इनक्यूबेटर, सोशल अल्फा द्वारा प्रबंधित 18 महीने का इनक्यूबेशन ट्रैक भी शामिल है। यह चरण स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और बाज़ार-पहुँच के अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत में नवीन स्वास्थ्य सेवा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक समर्थन सुनिश्चित होगा।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. RBI ने राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी।

सितंबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंज़ूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 20 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा और 13 मई, 2027 तक चलेगा, और उनका पारिश्रमिक RBI द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

• राम सुब्रमण्यम गांधी को हाल ही में यस बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें सितंबर 2022 में तीन साल के कार्यकाल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। RBI की मंजूरी से निजी क्षेत्र के इस बैंक में उनके निरंतर नेतृत्व को औपचारिक रूप मिल गया है।

• गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, गांधी यस बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन और निरीक्षण प्रदान करेंगे, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे और दिन-प्रतिदिन के परिचालन प्रबंधन में शामिल हुए बिना शासन प्रथाओं का समर्थन करेंगे।

Key Points:-

(i) आर. गांधी को RBI में व्यापक अनुभव है, उन्होंने 2014 से 2017 तक डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंकिंग विनियमन, वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन में नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

(ii) RBI के अलावा, गांधी ने तीन वर्षों तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। उन्होंने हैदराबाद स्थित बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) में निदेशक के पद पर भी कार्य किया और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास में योगदान दिया।

(iii) बैंकिंग क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, गांधी वित्तीय क्षेत्र में कई प्रमुख पदों पर रहे हैं। बैंकिंग प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय विनियमन में उनकी व्यापक विशेषज्ञता उन्हें यस बैंक के विकास और समेकन के इस दौर में एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है।

SPORTS

1. अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर और 3 बार आईपीएल हैट्रिक रिकॉर्ड धारक अमित मिश्रा ने 22 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।

4 सितंबर, 2025 को, अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, जिससे दो दशक से अधिक समय तक चले उनके करियर का अंत हो गया, जिसमें उन्होंने सभी प्रारूपों और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

• अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट मैचों में 76 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/71 रहा। उनके टेस्ट करियर की शुरुआत 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई, जहाँ उन्होंने खुद को एक कुशल लेग स्पिनर के रूप में स्थापित कर लिया, जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखता है।

• एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों (ODI) में, मिश्रा ने 36 मैच खेले और 64 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/48 रहा। उन्होंने 10 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (T20I) में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहाँ उन्होंने 3/24 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 16 विकेट लिए। उनके सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय करियर में लगातार मैच जिताने वाले प्रदर्शन शामिल रहे।

Key Points:-

(i) अमित मिश्रा का IPL करियर शानदार रहा है, उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) जैसी फ्रेंचाइजी के लिए खेला है। 162 मैचों में, उन्होंने 174 विकेट लिए, जिससे वह IPL इतिहास में 8वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए। गौरतलब है कि वह IPL इतिहास में तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं।

(ii) मिश्रा ने 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे, 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। विभिन्न प्रारूपों में उनके लंबे कार्यकाल ने भारतीय क्रिकेट में उनकी अनुकूलनशीलता और दृढ़ता को दर्शाया।

(iii) अपने करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में से एक, अमित मिश्रा 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। सभी प्रारूपों में उनकी उपलब्धियाँ, और IPL में उनकी विरासत, उन्हें भारत के सबसे सफल लेग स्पिनरों में से एक बनाती हैं।

App and Web Portal

1. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2025 पर असम में पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल 'द वल्चर नेटवर्क' लॉन्च किया।

2 सितंबर, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर, भारत ने असम से अपना पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल—गिद्ध नेटवर्क—का अनावरण किया। यह अग्रणी पहल भारतीय गिद्ध प्रजातियों पर शोध, जागरूकता और नागरिक-संचालित संरक्षण के लिए एक समेकित डिजिटल मंच प्रदान करती है।

• वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के संयुक्त प्रयास से विकसित यह पोर्टल एक व्यापक क्लाउड-आधारित ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, निःशुल्क डाउनलोड योग्य जागरूकता सामग्री और शोधकर्ताओं, संरक्षणवादियों, छात्रों और स्थानीय समुदायों की

सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए डिजिटल उपकरण प्रदान करता है।

• इस पहल को असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क, लासा फाउंडेशन, सुरक्षा समिति और समर्पित संरक्षणवादियों जैसे प्रमुख संगठनों से समर्थन मिला है - जिन्होंने मिलकर गिद्ध नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों को एकत्रित किया है।

Key Points:-

(i) लॉन्च समारोह में, डॉ. प्रशांत के. सैकिया (सेवानिवृत्त प्रोफेसर और पूर्व विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र, गुवाहाटी विश्वविद्यालय), प्रो. दंडधर शर्मा (वर्तमान विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग), रोहिणी बल्लव सैकिया (उप वन संरक्षक), डॉ. नारायण शर्मा (सहायक प्रोफेसर, कॉटन विश्वविद्यालय), और डॉ. ओइनम सुनंदा देवी (वैज्ञानिक अधिकारी, असम राज्य जैव विविधता बोर्ड) सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने पूरे भारत में संरक्षण प्रयासों को एकजुट करने में पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

(ii) इस अवसर पर विशेषज्ञों ने भारत की गिद्ध आबादी के लिए जारी खतरों पर भी चिंता जताई - शव विषाक्तता और डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग से लेकर आवास की हानि और सामाजिक गलत धारणाओं तक - उन्होंने पतली-चोंच वाले गिद्ध जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की गंभीर गिरावट पर प्रकाश डाला, जिनमें से केवल 800 परिपक्व गिद्ध ही बचे हैं।

(iii) वक्ताओं ने जमीनी स्तर पर भागीदारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और गिद्ध संरक्षण में नागरिक विज्ञान को शामिल करने का आग्रह किया। रणनीतियों में सुरक्षित प्रथाओं पर जागरूकता अभियान, निगरानी पहल और समुदायों और गिद्ध संरक्षण प्रयासों के बीच संबंध मज़बूत करने के लिए शैक्षिक पहुँच शामिल थी।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. RBI ने कॉस्मिक डॉन हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाने के लिए 'PRATUSH' रेडियोमीटर विकसित किया।

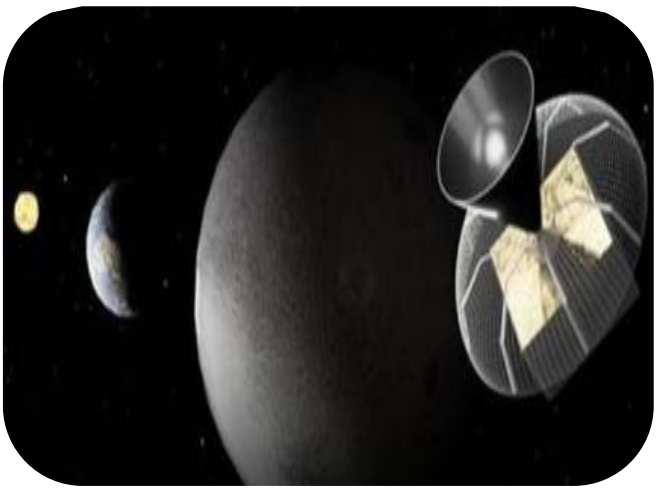

सितंबर 2025 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओएसएंडटी) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई) ने हाल ही में 'प्रातुष' (हाइड्रोजन से सिग्नल का उपयोग करके ब्रह्मांड के पुन: आयनीकरण की जांच) विकसित किया है, जो एक कॉम्पैक्ट रेडियोमीटर है जिसे कॉस्मिक डॉन से 21 सेंटीमीटर के धुंधले हाइड्रोजन सिग्नल का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• PRATUSH एक अंतरिक्ष पेलोड और कॉम्पैक्ट रेडियोमीटर है जिसे विशेष रूप से प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय उदय के दौरान हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित रेडियो संकेतों का पता लगाना है, जिससे शुरुआती तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांडीय विकास और ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।

• इस रेडियोमीटर को रमन अनुसंधान संस्थान (RRI) द्वारा खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष उपकरणों

में अपनी व्यापक विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए विकसित किया गया है। प्रतुश कॉम्पैक्ट है, जिससे इसका वजन, बिजली की खपत और संचालन संबंधी जटिलता कम होती है, जिससे यह चंद्रमा की कक्षा में इष्टतम अवलोकनों के लिए तैनात करने के लिए उपयुक्त है।

Key Points:-

(i) PRATUSH रास्पबेरी पाई तकनीक पर आधारित एक सिंगल-बोर्ड कंप्यूटर (SBC)-आधारित डिजिटल रिसीवर और एक फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट ऐरे (FPGA) चिप का उपयोग करता है। यह सेटअप ब्रह्मांडीय रेडियो डेटा की धाराओं को उच्च परिशुद्धता के साथ संसाधित करता है, जिससे कुछ मिलीकेल्विन (mK) तक के अत्यंत मंद संकेतों का पता लगाना संभव हो जाता है, जो इसकी असाधारण संवेदनशीलता को दर्शाता है।

(ii) इस मिशन को रेडियो-शांत वातावरण का लाभ उठाने के लिए विशेष रूप से चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर संचालित करने की योजना है। यह रणनीतिक स्थिति पृथ्वी-आधारित रेडियो संकेतों से होने वाले हस्तक्षेप को न्यूनतम करती है और 21-सेमी हाइड्रोजन रेखा का सटीक माप सुनिश्चित करती है, जो कॉस्मिक डॉन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

(iii) एक संदर्भ संकेत पर 352 घंटों तक किए गए प्रदर्शन परीक्षणों ने अत्यंत मंद ब्रह्मांडीय संकेतों का पता लगाने की PRATUSH की क्षमता की पुष्टि की है। यह विकास भारतीय खगोल भौतिकी के लिए एक प्रमुख तकनीकी उपलब्धि है, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नया उपकरण प्रदान करता है और ब्रह्मांडीय विकास पर वैश्विक शोध में योगदान देता है।

Static GK

Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Assam	मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा	राज्यपाल: लक्ष्मण आचार्य
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	अध्यक्ष: अभिषेक देव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Nepal	राजधानी: काठमांडू	मुद्रा: नेपाली रुपया
Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC)	निदेशक : माइकल ग्रीनस्टोन	मुख्यालय: शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
Reliance Industries Limited (RIL)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD): मुकेश अंबानी	मुख्यालय: मुंबई
WHO	उप महानिदेशक: माइकल रयान	मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Ministry of Education (MoE)	मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान	मुख्यालय: नई दिल्ली
ICICI Bank	CEO : संदीप बख्शी	मुख्यालय: मुंबई